RNI NO. : MAHHIN/2019/77511 मुंबई : सोमवार 29 जनवरी 2024 वर्ष 05 अंक 278 संपादक : फैसल शेख पृष्ठ : 4 कीमत : 03 रुपये

दैनिक
रोकठोक लेखनी
खबरें बे-रोकटोक

Read E Newspaper at Paper Boy App, Magzter App, Jio News App, Paytm App, Dailyhunt App

समाज में तनाव पैदा करना बंद करें...!

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का संभाजी ब्रिगेड पर पलटवार...

पुणे : मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा उनकी मांगें मान लिये जाने के बाद शनिवार को अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल खत्म कर दी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की कि जब तक मराठों को आरक्षण नहीं मिल जाता, तब तक उन्हें ओबीसी को प्राप्त सभी लाभ मिलेंगे। इसी बीच अब शिंदे उनके फैसले की आलोचना करने वाले संभाजी ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष मनोज आखरे के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि समाज में तनाव पैदा करने का काम न करें। यह सरकार सभी समाजों ने मिलकर बनाई है।

यह आम आदमी की सरकार है

सातारा में मीडिया से बातचीत के दौरान एकनाथ शिंदे ने कहा, मराठा समाज को कई वर्षों तक आरक्षण से वंचित रहना पड़ा। महागठबंधन की सरकार आम आदमी की सरकार है। मराठा समाज को आरक्षण मिले यह हमारी सरकार की भूमिका थी। लेकिन वो कानून के दायरे में हो, टिकाऊ हो और ओबीसी समाज के साथ अन्याय किए बिना आरक्षण देने का हमारा रुख कल था, आज है और कल भी रहेगा।

सीएम शिंदे ने कहा, ओबीसी और अन्य समाज के लोग भी हमारे हैं। साथ ही यह सरकार सभी समाजों से मिलकर बनी है। इसलिए एक को हटाकर दूसरे को देने का काम सरकार नहीं करेगी। मनोज जरांगे ने जो आंदोलन शुरू किया है, उसमें लाखों मराठा भाई शामिल हुए थे। कुनबी अभिलेख मिलने लगे हैं। नययमूर्ति शिंदे कमेटी इस पर काम कर रही है। सभी ने यह रुख अपनाया कि मराठा समाज को न्याय मिलना चाहिए। फिर भी मराठा समाज के साथ धोखा हुआ है ऐसी टिप्पणी करना और सर्वे पर सवाल उठाना बंद होना चाहिए।

सीएम शिंदे ने आगे कहा, मराठा समाज ने अनेक नेता खड़े किये, लेकिन नेताओं ने मराठा समाज को वंचित रखा। आज, जब अन्य समाजों के साथ अन्याय किए बिना मराठा समाज को आरक्षण देने का समय आ गया है, तो यह मेरा और सरकार का रुख है कि किसी को भी समाज में तनाव में पैदा करने का काम नहीं करना चाहिए।

क्या बोले थे मनोज आखरे...

गौरतलब है कि मनोज आखरे ने एकनाथ शिंदे पर मराठा समाज की प्रमुख मांगो को नजरअंदाज करने और धोखा देने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था, मराठा समाज की प्रमुख मांगों को नजरअंदाज कर यह अध्यादेश पारित किया गया है। ये बिल्कुल गलत है। सरकार को 57 लाख रिकॉर्ड कभी नहीं मिले। इसलिए सरकार ने मनोज जरांगे को गुमराह किया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अब तक जो भी कहा है वह पूरी तरह से झूठ है। मराठों और कुनबियों को अलग-अलग दिखाने की कोशिश की जा रही है। सरकार ने मराठा समाज को धोखा दिया गया है। मराठा समाज को ओबीसी में शामिल करने की मांग अभी भी अधूरी है। मनोज जरांगे को गुमराह किया जा रहा है, लेकिन ये उन्हें समझ नहीं रहा है।''

हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है..., चुनाव आते ही विरोध में उतरे राज ठाकरे

नवी मुंबई : शिवसेना से अलग होने के बाद अपनी नई पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) बनाने वाले राज ठाकरे ने हिंदी के विरोध के सहारे अपनी सियासत चमकाने की हर संभव प्रयास किया था, लेकिन उन्हें नाकामी ही हाथ लगी थी। उस नाकामी से सबक लेने के बजाय राज ने एक बार फिर से हिंदी के विरोध को हथियार बनाया है। उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा मानने से इनकार कर दिया। राज ठाकरे ने कहा मैं कट्टर मराठी हूं

रविवार को उन्होंने कहा कि भले ही हिंदी अच्छी भाषा होगी, लेकिन ह्लहिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है।'' बता दें कि नवी मुंबई के वाशी स्थित सिडको प्रदर्शनी केंद्र में रविवार (28 जनवरी) से शुरू हुए तीन दिवसीय विश्व मराठी सम्मेलन को संबोधित करने के दौरान राज ने सवाल उठाते हुए कहा कि मराठी में बोलने के दौरान लोग हिंदी का उपयोग क्यों करते हैं? राज इतने पर ही नहीं रुके। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि हमें हिंदी फिल्मों से मिली। लेकिन हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। राज ठाकरे ने कहा कि आपको लगा होगा, राज ठाकरे आएंगे, आपसे बात करेंगे, कई विषय सुझाएंगे, बताएंगे कि मराठी भाषा को कैसे आगे बढ़ाया जाए। लेकिन मैं आज आपके सामने इसलिए खड़ा हूं क्योंकि मैं कई सालों से मराठी के बारे में बात कर रहा हूं। शरीर के बाल मराठी भाषा के लिए गए हैं, मैं मराठी विषय के लिए ही जेल गया था। मैं अब भी वही बात कह रहा हूं, मैं बहुत कट्टर मराठी हूं। मेरे साथ भी संस्कार ऐसे ही हुए।

शिवसेना-यूबीटी नेता संजय राउत के भाई को ईडी का समन...

मुंबई : प्रवर्तन निदेशालय ने शिवसेना-यूबीटी के नेता संजय राउत के भाई संदीप राउत को समन भेजा है. संदीप राउत को कोरोना काल के दौरान हुए कथित खिचड़ी स्कैम मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है. उन्हें 30 जनवरी से पहले हाजिर होने को कहा गया है. बता दें कि ईडी ने अलग-अलग मामलों में इससे पहले शरद पवार के गुट वाली एनसीपी के नेताओं को भी समन जारी किया था जिसमें विधायक रोहित पवार का नाम भी शामिल है. बता दें कि इस मामले में शिवसेना-यूबीटी के नेता सूरज चव्हाण की गिरफ्तारी हो चुकी है. यह खिचड़ी स्कैम से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है.

मुंबई पुलिस की अपराध शाखा द्वारा दर्ज एफआईआर में कहा गया है कि कोरोना महामारी के दौरान प्रवासियों को खिचड़ी उपलब्ध कराने को लेकर बीएमसी ने जो ठेका दिया था उसमें अनियमितता बरती गई थी. पैकेट में तय माप से कम ही खिचड़ी होती थी.

इस मामले में होगी पूछताछ

बताया जा रहा है कि संदीप राउत से मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत बयान दर्ज किया जाएगा. इस मामले में पिछले साल शिवसेना-यूबीटी नेता अमोल कीर्तिकर से भी पूछताछ की जा चुकी है. अमोल कीर्तिकर पूर्व सांसद गजानन कीर्तिकर के बेटे हैं.

एक अन्य मामले में रोहित पवार से भी हुई है पूछताछ

संदीप राउत को इससे पहले 24 जनवरी को ईडी का समन भेजा गया था और चार दिन बाद एकबार फिर इस मामले में समन भेजा गया है. उन्हें मुंबई स्थित ईडी के दफ्तर में पेश होने कहा गया है. उधर, शरद पवार के पोते रोहित पवार को भी ईडी ने समन भेजा था उनसे ईडी ने करीब 11 घंटे पूछताछ की थी. यह महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था. इस संबंध में मुंबई पुलिस ने अगस्त 2019 में केस दर्ज किया था.

शिक्षक की हत्या करने वाला 22 वर्षीय व्यक्ति गिरफ्तार

मीरा-भयंदर: वसई में अपने अपार्टमेंट में अपने परिचित की कथित तौर पर हत्या करने और मौत को आत्महत्या बताकर अपने अपराध को छिपाने की कोशिश करने से पहले भाग जाने के 24 घंटे से भी कम समय में, 22 वर्षीय आरोपी को अनार्ला तटीय क्षेत्र के गोरेगांव से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस। पुलिस के अनुसार उन्हें शिकायतकर्ता अनिल चंदया ने सूचित किया था कि उनका छोटा भाई नागेश (48) जो पेशे से शिक्षक था, वसई के प्रीमियम पार्क इलाके में अपने अपार्टमेंट में मृत पाया गया था, उसकी दोनों कलाइयां कटी हुई थीं। शुरूआत में 22 जनवरी को अनार्ला पुलिस स्टेशन में एक आकस्मिक मौत रिपोर्ट (एडीआर) दर्ज की गई थी। जांच के दौरान, पुलिस मृतक के मोबाइल फोन का पता नहीं लगा सकी, इसके अलावा शव मिलने से कुछ घंटे पहले एक अज्ञात व्यक्ति को संदिग्ध तरीके से इमारत में प्रवेश करते और निकलते देखा गया था, जो हत्या की संभावना की ओर इशारा करता है।

संपादकीय / लेख

फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

गठबंधन से पहले अलगाव...

हमने पहले भी लिखा है कि विपक्ष का गठबंधन टूटने के लिए बनता है। चूंकि विपक्ष की नियति टूटने की है, लिहाजा बार-बार गठबंधन करना पड़ता है। यह नियति हम जनता पार्टी के दौर से देखते आ रहे हैं। इस बार 'इंडिया' का प्रयोग कुछ भिन्न और व्यापक लग रहा था, लेकिन दो अलगाव ऐसे घोषित किए गए हैं कि विपक्षी गठबंधन की संभावनाएं प्रभावहीन लगती हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस और पंजाब में भगवंत मान ने आम आदमी पार्टी (आप) की ओर से घोषणाएं की हैं कि वे अकेले ही सभी सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। अलबत्ता उन्होंने 'इंडिया' का हिस्सा बने रहने की भी घोषणाएं की हैं। अपने प्रभाव क्षेत्रों के बाहर गठबंधन के मायने क्या हैं? यदि ये घोषणाएं 'अंतिम' हैं, तो भाजपा की चुनावी संभावनाएं बढ़ सकती हैं। ममता और भगवंत मान दोनों ही अपने-अपने राज्य के मुख्यमंत्री हैं। आश्चर्य यह है कि बंगाल में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, के प्रति अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते रहे हैं। वह छुटभैया नेता नहीं हैं, बल्कि लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता हैं। वह ममता बनर्जी को 'अवसरवादी नेता' करार देते रहे हैं और बार-बार बयान देते हैं कि ममता कांग्रेस की कृपा और मदद से ही पहली बार सत्ता में आई थीं। कांग्रेस अकेले ही चुनाव लड़ने में सक्षम है। ममता 'इंडिया' की भीतरी राजनीति से क्षुब्ध थीं। उनके प्रत्येक प्रस्ताव को खारिज किया गया। गठबंधन में वाममोर्चे के नेताओं का प्रभाव ज्यादा है और वे हरेक बैठक को 'तारपीडो' करते रहे हैं। ममता का आरोप है कि राज्य में कांग्रेस की रैलियां की जा रही हैं। उनके खिलाफ जहर उगला जा रहा है। राहुल गांधी की 'न्याय यात्रा' की न तो उन्हें जानकारी दी गई और न ही कोई आमंत्रण मिला। बंगाल में 'न्याय यात्रा' और राहुल गांधी के जो पोस्टर लगाए गए थे, ममता की घोषणा के बाद उन्हें फाड़ना शुरू कर दिया गया। दोनों दलों के बीच जहरीला अलगाव इस हद तक पहुंच चुका है।

अंततः ममता ने फैसला किया कि उनकी तृणमूल कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के साथ, कोई गठबंधन नहीं करेगी और सभी 42 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। हालांकि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बयान देकर पार्टी का नरम रुख जताया कि ममता के बिना 'इंडिया' गठबंधन की कल्पना तक नहीं की जा सकती। बहरहाल तृणमूल कांग्रेस बंगाल की सबसे मजबूत राजनीतिक ताकत है। 2019 के आम चुनाव में 43 फीसदी से ज्यादा वोट हासिल कर उसके 22 सांसद जीते थे, जबकि कांग्रेस के 5.5 फीसदी वोट के साथ मात्र 2 सांसद ही संसद तक पहुंच पाए थे। वाममोर्चे को करीब 7.5 फीसदी वोट मिले थे, लेकिन सांसद के तौर पर 'शून्य' ही नसीब हुआ। भाजपा को 40 फीसदी से ज्यादा वोट मिले थे और उसके पहली बार 18 सांसद चुने गए। दरअसल विपक्षी गठबंधन अपने अस्तित्व के करीब 7 माह के दौरान चाय-नाश्ते पर बैठकें तो कर सका, लेकिन सीटों के बंटवारे, सचिवालय, संयोजक, साझा न्यूनतम कार्यक्रम, साझा नारा, ध्वज आदि पर आज तक सहमत नहीं हो सका है। अब तो अलगाव की नौबत भी आ गई है। बंगाल के अलावा, पंजाब की घोषणा भी अलगाववादी है। ऐसी स्थिति में मोदी का मुकाबला कैसे होगा?

+91 99877 75650
editor@rokthoklekhaninews.com
Faisal Shaikh @faisalshaikh_91

मालवणी पुलिस स्टेशन परिसर के ऑडियो-वीडियो सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित करने का निर्देश...

मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय ने मुंबई पुलिस को रामनवमी उत्सव के दौरान 30 मार्च 2023 को मालवणी क्षेत्र में भड़की सांप्रदायिक हिंसा के संबंध में मालवणी पुलिस स्टेशन परिसर के ऑडियो-वीडियो सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ का 22 जनवरी का आदेश एक सामाजिक कार्यकर्ता मुहम्मद जमील मर्चेंट द्वारा दायर याचिका पर आया। इस मामले में आरोपी बनाए गए मर्चेंट ने दलील दी है कि उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है, जबकि वह वास्तव में मलाड पश्चिम के अल्पसंख्यक बहुल इलाके मालवणी में उस रात तनाव कम करने की कोशिश कर रहे थे।

याचिकाकर्ता ने कहा कि मुंबई पुलिस सीसीटीवी फुटेज को रोक रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि इससे वह बरी हो जाएगा क्योंकि वह निर्दोष है। मर्चेंट ने आगे दावा किया कि मालवणी पुलिस स्टेशन में मौजूद कुछ राजनीतिक नेताओं ने कथित तौर पर पुलिस पर एफआईआर में उनका नाम शामिल करने के लिए दबाव डाला था, हालांकि वह वास्तव में अपने भवन परिसर के बाहर इकट्ठा हुई भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस की मदद और सहयोग कर रहे थे। मर्चेंट की ओर से वकील संजीव कदम, प्रशांत राउल और बी.वी. बुखारी पेश हुए, जबकि राज्य का प्रतिनिधित्व विशेष लोक अभियोजक कौशिक म्हात्रे और सहायक लोक अभियोजक आर.एम. पेठे ने किया।

उच्च न्यायालय में अपनी याचिका के अलावा, मर्चेंट ने पहले मुंबई के संरक्षक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, संयुक्त पुलिस आयुक्त सत्यनारायण चौधरी, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (उत्तर क्षेत्र) राजीव जैन, पुलिस उपायुक्त अजय बंसल और मालवणी पुलिस के खिलाफ महाराष्ट्र लोकायुक्त और राज्य मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। उच्च न्यायालय ने 9 अगस्त, 2023 को पुलिस डीसीपी (जोन-क) को 30 मार्च की रात 10.30 बजे से 31 मार्च की सुबह 10 बजे तक यानी लगभग 12 घंटों के लिए मालवणी पुलिस में स्थापित 21 कैमरों से सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को संरक्षित करने का निर्देश दिया था। अदालत ने याचिकाकर्ता को, जिसे फुटेज की प्रतियां प्रदान की गईं झ सीसीटीवी वीडियो/ऑडियो फुटेज पर सुप्रीम कोर्ट के निदेर्शों के उल्लंघन के मद्देनजर एक स्वतंत्र मूल याचिका दायर करने की भी अनुमति दी।

शिक्षक की हत्या के 24 घंटे के भीतर...

22 वर्षीय परिचित को गिरफ्तार

मुंबईः एक शिक्षक की हत्या के 24 घंटे के भीतर, अनार्ला पुलिस ने पीड़ित के 22 वर्षीय परिचित को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अधिक जानकारी दिए बिना कहा कि प्रथम दृष्टया, ऐसा प्रतीत होता है कि हत्या पैसे से संबंधित एक मामूली झगड़े का नतीजा है, क्योंकि आगे की जांच जारी है।

आरोपी अलफरन चंद उस्मान खान, जो फिल्म उद्योग में छोटे-मोटे काम करता है, पर हत्या को आत्महत्या बताकर अपने अपराध को छुपाने का प्रयास करने का भी आरोप है। पुलिस के मुताबिक, अनिल चंदया ने उन्हें सूचित किया कि उनका छोटा भाई 48 वर्षीय नागेश वसई के प्रीमियम पार्क इलाके में अपने अपार्टमेंट में मृत पाया गया है। प्रारंभ में, 22 जनवरी को एक आकस्मिक मृत्यु रिपोर्ट (एडीआर) दर्ज की गई थी।

जांच के दौरान पुलिस को मृतक का मोबाइल फोन नहीं मिल सका. इसके अलावा, शव मिलने से कुछ घंटे पहले एक अज्ञात व्यक्ति को संदिग्ध तरीके से इमारत में प्रवेश करते और निकलते देखा गया था। वरिष्ठ निरीक्षक विजय पाटिल के नेतृत्व में एक टीम ने कॉल डेटा रिकॉर्ड की जाँच की और संदिग्ध के मोबाइल नंबर को निगरानी पर रखा। सामने आया कि संपर्क विरार और गोरेगांव के बीच सक्रिय था. फिर विशेष टीमों को तैनात किया गया और खान को आखिरकार 23 जनवरी को बांगुर नगर मेट्रो स्टेशन के पास पकड़ लिया गया। राजस्थान का मूल निवासी, आरोपी गोरेगांव के मीठा नगर इलाके में रहता था। उसने नागेश की कलाई काटकर और बाद में गला घोंटकर हत्या करने की बात कबूल की इस बीच, एडीआर को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या के मामले में बदल दिया गया है।

बालासाहेब थोराट और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को वीबीए और अन्य समान विचारधारा वाले दलों के साथ बातचीत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई

मुंबईः महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी रमेश चेन्निथला ने शनिवार को कहा कि नाना पटोले सहित उनकी पार्टी की राज्य इकाई के नेतृत्व को प्रकाश आंबेडकर के नेतृत्व वाले वंचित बहुजन अघाड़ी (वीबीए) और अन्य समान विचारधारा वाले दलों के साथ सीट-बंटवारे पर बातचीत करने के लिए कहा गया है. यह बयान लोकसभा चुनाव के लिए सीट-बंटवारे पर बातचीत के लिए महा विकास अघाड़ी गठबंधन के नेताओं (महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख पटोले और शरद पवार के नेतृत्व वाली राकांपा और शिवसेना (यूबीटी) के नेता) की ओर से दिये गये आमंत्रण को आंबेडकर द्वारा अस्वीकार करने के कुछ दिनों बाद आया है. आंबेडकर ने यह भी दावा किया कि पटोले के पास इस तरह की बातचीत करने की कोई शक्ति नहीं थी. उत्तर महाराष्ट्र में पार्टी की लोकसभा चुनाव तैयारियों की समीक्षा के बाद यहां पत्रकारों से बात करते हुए चेन्निथला ने कहा कि पटोले, राज्य विधायक दल के नेता बालासाहेब थोराट और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को वीबीए और अन्य समान विचारधारा वाले दलों के साथ बातचीत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. चेन्निथला ने बताया कि राहुल गांधी की 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा'धुले से महाराष्ट्र में प्रवेश करेगी.

मुंबई के लालबाग फ्लाईओवर पर हादसा, डिवाइडर से टकराई बाइक... 2 लोगों की मौत!

मुंबई : मुंबई के लालबाग फ्लाईओवर पर हुए सड़क हादसे में दो बाइक सवारों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि शनिवार को लालबाग फ्लाईओवर पर दोपहिया वाहन के डिवाइडर से टकरा जाने से दुर्घटना हुई। पुलिस को शक है कि दक्षिण मुंबई की ओर जा रहे दोनों नशे में थे और किसी पार्टी से लौट रहे थे। मृतकों की पहचान 25 वर्षीय रुशिकेश सालकर और 40 वर्षीय शैलेश सईद के तौर पर हुई है। दोनों साकीनाका इलाके के निवासी हैं। पुलिस के मुताबिक, शनिवार को तड़के करीब तीन बजे सूचना मिली कि लालबाग ओवरब्रिज पर डिवाइडर से एक बाइक टकरा गई है।

कालाचौकी पुलिस और भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची और दोनों पीड़ितों को दक्षिण की ओर जाने वाली लेन पर डिवाइडर से टकराने के बाद अचेत अवस्था में पाया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गयी। पुलिस अधिकारी ने कहा, दोनों को जेजे अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

दैनिक रोकठोक लेखनी
खबरें बे-रोकटोक
मुंबई : सोमवार 29 जनवरी 2024

उत्तराखंड के मदरसे के बच्चे पढ़ेंगे प्रभु श्रीराम की कहानी...

नए सिलेबस में होने जा रहा बड़ा बदलाव

उत्तराखंड : उत्तराखंड के मदरसों के सिलेबस में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने बताया है कि मदरसे में बच्चों को भगवान श्रीराम की कहानियां पढ़ाई जाएंगी. वक्फ बोर्ड के चीफ शादाब शम्स ने बताया कि इस साल मार्च में शुरू होने वाले सेशन में नए सिलेबस को लागू किया जाएगा. उन्होंने बताया कि भगवान श्रीराम एक ऐसे चरित्र हैं जिनके बारे में हर एक को पता होना चाहिए और उनको फॉलो करना चाहिए. जान लें कि उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड के तहत 117 मदरसे चलते हैं.

वक्फ बोर्ड के चीफ शादाब शम्स ने कहा कि पिता को वादा पूरा करने में मदद के लिए भगवान श्रीराम ने सिंहासन छोड़ दिया था और वन चले गए थे. किसको भगवान श्रीराम के जैसा बेटा नहीं चाहिए होगा? उन्होंने आगे कहा कि मदरसे के स्टूडेंट्स को पैगंबर मोहम्मद के साथ ही भगवान श्रीराम की जिंदगी के बारे में भी पढ़ाया जाएगा.

मदरसे में अच्छे संस्कार सीखेंगे बच्चे

शादाब शम्स ने कहा कि भगवान श्रीराम के जो गुण हैं उन्हें हर किसी को फॉलो करना चाहिए. भले ही वो किसी भी धर्म का हो. भगवान श्रीराम की कहानियों से बच्चे अच्छे गुण और संस्कार सीखेंगे. देहरादून, ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार और नैनीताल के जिलों में चलने वाले मदरसों में श्रीराम की कहानियां बच्चों को पढ़ाई जाएंगी.

'है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज'

इस मौके पर वक्फ बोर्ड के चीफ शादाब शम्स ने अल्लामा इकबाल को भी याद किया. उन्होंने कहा कि इकबाल ने कहा था कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम-ए-हिंद. शम्स ने बताया कि श्रीराम के साथ बच्चे लक्ष्मण जी और माता सीता के बारे में भी जानेंगे, जिन्होंने महल के ऐशो-आराम को छोड़कर भगवान श्रीराम के साथ वन में जाने का फैसला किया था. वक्फ बोर्ड के चीफ शादाब शम्स ने आगे कहा कि कौन ही होगा जो अपने बच्चों को भगवान श्रीराम के गुणों वाला नहीं बनाना चाहेगा.

नीतीश कुमार 9वीं बार बने बिहार के मुख्यमंत्री... इन 8 मंत्रियों ने भी ली शपथ

बिहार : नीतीश कुमार ने आज बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. उन्होंने नौवीं बार बतौर सीएम शपथ ली. जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आज ही महागठबंधन से अलग होने का एलान कर एनडीए ज्वाइन कर लिया था. नीतीश कुमार के साथ आठ और मंत्रियों ने शपथ ली है. इसमें सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी हैं जिन्हें बतौर डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली है. डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लेने से पहले सम्राट चौधरी को बीजेपी ने विधायक दल का नेता और विजय सिन्हा को उपनेता चुना था. इन दोनों के अलावा बीजेपी की तरफ से डॉ. प्रेम कुमार, जेडीयू से विजय कुमार चौधरी, श्रवण कुमार, विजेंद्र यादव, हम से संतोष कुमार सुमन और निर्दलीय सुमित कुमार सिंह ने भी मंत्री पद की शपथ ली.

राबड़ी सरकार में मंत्री रह चुके हैं सम्राट

बिहार के मुंगेर से ताल्लुक रखने वाले सम्राट चौधरी पहले भी बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं. सम्राट राबड़ी देवी सरकार में मंत्री रहे हैं. वह राजनीतिक परिवार से आते हैं. उनके पिता शकुनी चौधरी सात बार के विधायक रहे हैं जबकि मां पार्वती देवी भी विधायक रही हैं. हालांकि छह साल पहले ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी और पिछले साल मार्च उन्हें बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया था. वह बिहार विधान परिषद में बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं.

विजय कुमार सिन्हा की बात करें तो वह बीजेपी-जेडीयू की पूर्ववर्ती सरकार में श्रम मंत्री रहे हैं. वह 2010 से लखीसराय विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. वह वर्ष 2020 से 2022 तक विधानसभा स्पीकर रहे हैं. विजय सिन्हा विधायक बनने से पहले बीजेपी संगठन का काम देखते थे. उन्हें साल 2000 में बीजेवाईएम का प्रदेश प्रभारी बनाया गया था. वह बीजेपी के किसान मोर्चा से भी जुड़े रहे हैं. मंत्रियों में संतोष कुमार सुमन का नाम भी बेहद खास है. वह पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बेटे हैं. वह फिलहाल एचएएम के विधान परिषद सदस्य हैं. वह 2020-2022 के बीच एनडीए सरकार में मंत्री रहे हैं. बिहार के नवगठित मंत्रियों के समूह में जातिगत समीकरण पर विशेष ध्यान रखा गया है. सीएम नीतीश कुमार जहां कुर्मी समाज से आते हैं तो विजय कुमार चौधरी भूमिहार हैं और श्रवण कुमार भी कुर्मी समाज से हैं.

रायगढ़ जिले में एक फर्जी कॉल सेंटर पर छापेमारी...

मुंबई : महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में एक फर्जी काल सेंटर पर छापेमारी कर केंद्रीय योजना के तहत ऋण दिलाने में मदद करने के बहाने लोगों को ठगने के आरोप में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई मुंबई पुलिस ने की है। पुलिस के अनुसार, छापेमारी के दौरान पुलिस ने जालसाजों से लगभग 58 लाख रुपये की नकदी और कीमती सामान भी जब्त किया और ये पनवेल के एक फ्लैट से काम कर रहे थे। एक अधिकारी ने बताया कि आरोपित प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण दिलाने का वादा कर लोगों से ठगी करते थे। उन्होंने कहा कि पुलिस ने यह कार्रवाई मीना मिरगुले की शिकायत पर की। महिला ने कहा है कि उसने फेसबुक पर कम ब्याज पर ऋण के बारे में एक विज्ञापन देखा। इसके बाद उसने विज्ञापन में दिए गए मोबाइल नंबर पर फोन किया।

मिरगुले ने पुलिस को बताया कि फोन करने पर लोगों ने उससे कई दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा और उससे 40 हजार रुपये भी वसूले। जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है और उसने अंधेरी पुलिस से संपर्क किया।

अधिकारी के अनुसार, तकनीकी साक्ष्य समेत विभिन्न इनपुट का इस्तेमाल करते हुए पुलिस ने बुधवार को पनवेल में फर्जी काल सेंटर का पदार्फाश किया और 10 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने जालसाजों के पास से 38 मोबाइल फोन, 61 डेबिट कार्ड, 20 चेकबुक, 37 पासबुक और 48 सिम कार्ड बरामद किए हैं। इसके साथ ही 58 लाख रुपये की नकदी और कीमती सामान भी जब्त किया।

जवानों ने घायल महिला की मदद कर जीत लिया दिल

रायगढ़: मुंबई पुलिस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें एक घायल महिला ट्रैकर को त्वरित प्रतिक्रिया टीम द्वारा प्रदान की गई त्वरित सहायता के दृश्य दिखाए गए हैं। यह घटना रायगढ़ जिले के करनाला किले में हुई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए मुंबई पुलिस ने कहा, ''परिस्थिति चाहे जितनी भी हो, त्वरित प्रतिक्रिया!''

वीडियो में आप मुंबई पुलिस की क्विक रिस्पॉन्स टीम के रंगरूटों की एक टीम को कनार्ला किले के जंगल में एक घायल महिला को ले जाते हुए देख सकते हैं। वे उसे सावधानी से ले जाते हुए देखे जा सकते हैं क्योंकि वह अपनी चोट

को लेकर चिंतित दिख रही है।घटना और प्रतिक्रिया टीम द्वारा महिला को प्रदान की गई सहायता की प्रकृति के बारे में अधिक जानकारी देते हुए, मुंबई पुलिस ने लिखा, ''हमारी त्वरित प्रतिक्रिया टीम के नए सदस्य, करनाला किले में प्रशिक्षण के दौरान एक ट्रेक से नीचे उतर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक ट्रैकर की हड्डी टूट गई है उसकी टांग।''

विभाग ने कहा, ''कोई बचाव विकल्प उपलब्ध नहीं होने के कारण, रंगरूटों ने अपने ट्रैकसूट के साथ एक अस्थायी स्ट्रेचर बनाया और घायल महिला को 2 घंटे में बेस कैंप ले आए। उसे चिकित्सा सहायता के लिए विधिवत अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। समय पर सोच और त्वरित कार्रवाई की गई'' मौके पर मौजूद क्विक रिस्पांस टीम के सदस्यों ने घायल ट्रेकर को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाने में मदद की। 26 जनवरी को मुंबई पुलिस की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि शिकायत दर्ज कराने के 48 घंटे बाद भी उन्हें शिकायत की प्रति नहीं मिली. एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर मुंबई पुलिस को 'बेकार'करार देते हुए निखिल वागले ने कहा कि माहिम पुलिस स्टेशन किसी काम का नहीं है। उनके पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए, मुंबई पुलिस के आधिकारिक अकाउंट ने वागले के आरोपों को खारिज कर दिया और उन्हें ''उचित'' भाषा का उपयोग करने की सलाह दी।वागले ने मराठी में पोस्ट किया, ''मुंबई पुलिस बेकार है। 48 घंटे हो गए हैं और शिकायत की प्रति नहीं मिली है। माहिम पुलिस स्टेशन को कबाड़ बाजार में बिक्री के लिए रखा जाना चाहिए।''

इंडिया अलायंस में सिर्फ डॉट ही डॉट है, स्पीड ब्रेकर है - प्रफुल्ल पटेल

मुंबई। NCP के वरिष्ठ नेता संसद प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार NDA में आते हैं तो उनका स्वागत है, बहुत खुशी होगी पहले भी वो NDA के घटक रहे हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बारे में हरदम अच्छे भाव रखते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष केवल मोदी जी के विरोध में जुटा है, मोदी जी को हटाना यह कोई मकसद नहीं होता है। ठबंधन का इंडिया का जो नाम दिया है उसमें सिर्फ डॉट ही डॉट है, स्पीड ब्रेकर है। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि उन्हें खुशी है कि नीतीश जी यह फैसला जल्द से जल्द लेते हैं तो और बेहतर होगा।

NCP के सांसद प्रफुल्ल पटेल ने आगे कहा कि इंडिया अलायंस की पहली बैठक नीतीश जी के निमंत्रण पर वह पटना

गए थे लेकिन वहां पर जो बातचीत हो रही थी उससे ऐसा नजर आ रहा था कि केवल मोदी जी का विरोध करने के लिए बैठक है। एकमात्र मकसद था कि मोदी हटाओ । ये देश को क्या बताना चाहते हैं? देश का विकास कैसे होगा, देश की समस्या कैसे दूर होगी, इसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं था, बस फोटो खिंचवाओ, देश के सामने पॉजिटिव एजेंडा कुछ नहीं था। इस संबंध में किसी की रुचि नहीं थी। मोदी जी को हटाओ, बस एक यही एजेंडा था। वहीं राम मंदिर के सवाल पर प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि रामजी का मंदिर वहां पर बनना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था जिसे सभी समुदाय ने स्वीकार किया। कुछ भी गलत नहीं है। अब स्वाभाविक है मोदी जी हैं तभी यह सब संभव हो रहा है।

महाराष्ट्र के गठबंधन के संबंध में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और एनसीपी के बीच कोई औपचारिक बैठक सीटों के बंटवारे में अभी नहीं हुई है लेकिन आने वाले दिनों में हो जाएगी। महाराष्ट्र में महायुति के बीच अच्छे तरीके से समन्वय रखते हुए सीटों का बंटवारा हो जाएगा।

दैनिक रोकठोक लेखनी
खबरें बे-रोकटोक
मुंबई : सोमवार 29 जनवरी 2024

महाराष्ट्र के राज्यपाल ने दुनिया भर में मराठी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने का आ'ान किया

ठाणे : महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस ने दुनिया भर में मराठी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक सामूहिक पहल की आवश्यकता पर बल दिया है। बैस शनिवार को नवी मुंबई में विश्व मराठी सम्मेलन-2024 के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आगामी वर्षों में भारत को दुनिया की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करने तथा देश में भाषाई विविधता को संरक्षित करने एवं बढ़ावा देने के महत्व को सुदृढ़ करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।

बैस ने महाराष्ट्र की सांस्कृतिक समृद्धि को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के प्रयास के तहत लोगों से सामूहिक रूप से 'अमृतवाणी मराठी'के

गुणों को दुनिया भर में फैलाने की अपील की। उन्होंने संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, चक्रधर स्वामी, संत तुकाराम, संत रामदास और महाराष्ट्र के सांस्कृतिक ताने-बाने को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने अन्य विभूतियों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। बैस ने ''दुनिया भर में मराठी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक पहल'' पर जोर दिया।

मराठी सहित क्षेत्रीय भाषाओं के सामने आने वाली चुनौतियों को दूर करने को लेकर उन्होंने अंग्रेजी के बढ़ते प्रभाव पर चिंता व्यक्त की और क्षेत्रीय भाषाओं को संरक्षित करने तथा बढ़ावा देने, इसके इस्तेमाल तथा सीखने के लिए जनता को प्रोत्साहित करने की जरूरत को रेखांकित किया। राज्यपाल ने कहा, ''एक भाषा तब लोकप्रिय होती है जब इसे जनता द्वारा अपनाया जाता है और प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा इसे सिखा जाता है।'' इस अवसर पर राज्य के मंत्री दीपक केसरकर भी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में अगले तीन दिन संगीत, साहित्य, मनोरंजन, पुस्तक पाठ और महाराष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत पर केंद्रित विभिन्न सत्र आयोजित होंगे।

पीठासीन अधिकारियों को दलगत राजनीति से ऊपर रहना चाहिए

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा है कि विधायिका के पीठासीन अधिकारी का ''मुख्य दायित्व'' निर्वाचित प्रतिनिधियों को स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति देते समय निष्पक्ष और दलगत राजनीति से ऊपर रहना है। शनिवार को यहां 84वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में बोलते हुए, अयोग्यता याचिकाओं पर अपने हालिया फैसले पर शिवसेना (यूबीटी) की कड़ी आलोचना का सामना करने वाले नार्वेकर ने यह भी कहा कि संवैधानिक कार्यालयों को राजनीतिक झगड़े में नहीं घसीटा जाना चाहिए।

''हम सभी राजनीतिक प्रक्रिया में

हितधारक हैं, लेकिन (एक ही समय में) बोलने के तरीके से इससे अलग हैं। एक पीठासीन अधिकारी का मुख्य दायित्व निर्वाचित प्रतिनिधियों को बोलने की अनुमति देते समय निष्पक्ष, दलगत राजनीति से ऊपर रहना है। उनके विचार स्वतंत्र रूप से हैं,'' उन्होंने कहा।

हाल ही में, लोगों द्वारा पीठासीन अधिकारियों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले सामने आए हैं, उन्होंने कहा, ''मैं किसी भी मतभेद का स्वागत करता हूं, लेकिन महसूस करता हूं कि इसे सम्मानजनक तरीके और भाषा में व्यक्त किया जाना चाहिए।'' इस महीने की शुरूआत में, नार्वेकर को उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिव सेना (यूबीटी) से गंभीर हमले का सामना करना पड़ा था, जब उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को ''असली'' शिव सेना के रूप में मान्यता देने का फैसला सुनाया था, जबकि दोनों द्वारा दायर अयोग्यता याचिकाओं पर सुनवाई की थी।

जमा से ज्यादा बैंकों के ऋण में हुई वृद्धिः RBI

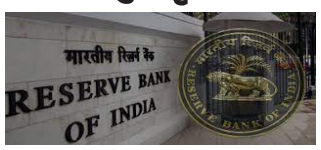

मुंबई : आरबीआई के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2024 के पहले पखवाड़े में बैंकों की ऋण और जमा वृद्धि के बीच का अंतर सितंबर 2023 के आखिरी पखवाड़े की तुलना में बढ़ गया है। 12 जनवरी, 2024 तक साल-दर-साल क्रेडिट और जमा वृद्धि क्रमशः 19.93 प्रतिशत और 12.84 प्रतिशत थी, जो कि 7.09 प्रतिशत अंकों के अंतर को दशार्ती है, जैसा कि भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति के बारे में आरबीआई के आंकड़ों से पता चलता है। बयान के अनुसार, 12 जनवरी, 2024 को समाप्त समीक्षा पखवाड़े के दौरान अनुसूचित बैंकों का बकाया ऋण 10,277 करोड़ रुपये बढ़ गया, जबकि जमा में 98,848 करोड़ रुपये की गिरावट आई।

70 वर्षीय व्यक्ति से 31.5 लाख की ठगी, FIR दर्ज

मुंबईः पुलिस ने शिकायतकर्ता से -31.35 लाख की धोखाधड़ी करने के आरोपी एक व्यक्ति के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।शिकायतकर्ता, 70 वर्षीय गोविंद गुप्ता का आरोप है कि उन्हें गणेश पाटेकर नाम के एक व्यक्ति ने धोखा दिया था, जिसने खुद को सरकारी मंत्रियों का करीबी सहयोगी बताया था और गुप्ता को साइबर सुरक्षा से संबंधित सरकारी अनुबंध देने का वादा किया था।

आजाद मैदान पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, गुप्ता ने अपनी शिकायत में कहा है कि उनके परिचित हीरालाल वाडकर ने उन्हें पाटेकर से मिलवाया था और दावा किया था कि पाटेकर के मुंबई और दिल्ली में सरकारी नेताओं के साथ प्रभावशाली संबंध थे। पाटेकर ने गुप्ता को गृह मंत्री और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ अपने कथित संबंधों का लाभ उठाकर साइबर

सुरक्षा अनुबंध हासिल करने की क्षमता का आश्वासन दिया।पाटेकर ने इन उच्च पदस्थ अधिकारियों के साथ बैठक की सुविधा के लिए गुप्ता से धन का अनुरोध किया। फरवरी 2023 में, पाटेकर, वाडकर और संजय सोनावणे नाम के एक अन्य व्यक्ति के साथ गुप्ता के कार्यालय गए। उन्होंने गुप्ता को कफ परेड में एक आवासीय फ्लैट के बारे में सूचित किया और दावा किया कि यह भारत के शत्रु संपत्ति संरक्षक, नई दिल्ली के अधीन है और जल्द ही इसकी नीलामी की जाएगी। पाटेकर ने फ्लैट खरीदने और इसे लाभ के लिए बेचने का प्रस्ताव रखा, जिसे आपस में साझा किया जाएगा। जैसे ही योजना शुरू हुई, पाटेकर ने गुप्ता को अपनी बेटी की बीमारी के बारे में सूचित किया और उसके इलाज के लिए धन का अनुरोध किया। गुप्ता ने कई किस्तों में -30 लाख नकद प्रदान किए और पाटेकर के लिए -1.35 लाख का एक मोबाइल फोन खरीदा। हालाँकि, जटिलताएँ पैदा हुईं और गुप्ता को एहसास हुआ कि उन्हें धोखा दिया जा रहा है, उन्होंने अपने पैसे वापस मांगना शुरू कर दिया।जून 2023 में, पाटेकर ने गुप्ता को चार चेक भेजे, लेकिन अपर्याप्त धनराशि के कारण वे बाउंस हो गए। चेक वापस आने पर गुप्ता ने आजाद मैदान पुलिस को घटना की सूचना दी। पाटेकर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात), 419 (प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी), और 420 (धोखाधड़ी) के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है, और धोखाधड़ी गतिविधियों को संबोधित करने के लिए एक जांच चल रही है।

नवी मुंबई में क्रेन से कुचलकर 20 वर्षीय मजदूर की दर्दनाक मौत!

ऑपरेटर के खिलाफ शिकायत दर्ज

ठाणे : महाराष्ट्र के नवी मुंबई शहर में एक 20 वर्षीय मजदूर की क्रेन से कुचलकर मौत हो गई। पुलिस ने रविवार को बताया कि घटना शनिवार सुबह करीब 11.30 बजे खारघर इलाके में हुई। घटना तब हुई जब मजदूर उस जगह पर एक केबल ड्रम को धकेल रहा था जहां खुदाई चल रही थी, तभी गलती से उसका पैर फिसल गया और वह क्रेन के पास सड़क पर गिर गया।

मजदूर की कुचलकर मौत

खारघर पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने कहा, उस समय, एक क्रेन ऑपरेटर ने मशीन को आगे बढ़ा दिया, जिससे मजदूर की कुचलकर मौत हो गई। नवी मुंबई के बेलापुर इलाके के रहने वाले मृतक की पहचान सुनील नरसीमा तांगड़ी के रूप में हुई है।

इन धाराओं पर दर्ज हुई शिकायत

मृत पीड़ित के भाई की शिकायत के आधार पर, क्रेन ऑपरेटर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304ए (लापरवाही से मौत का कारण बनना), 279 (तेज गाड़ी चलाना), 337 (जीवन को खतरे में डालकर चोट पहुंचाना), 338 (गंभीरता से चोट पहुंचाना)और मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधान के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा कि शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया गया है और घटना की जांच की जा रही है।

'मराठा आरक्षण के मुद्दे पर उट शिंदे के फैसले से संतुष्ट नहीं', अजित गुट के नेता ने उठाए सवाल

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल ने मराठा आरक्षण की मांग को लेकर सीएम शिंदे के फैसले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि वह मराठा आरक्षण मुद्दे पर राज्य सरकार के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं।

छगन भुजबल का दावा

भुजबल ने दावा किया है कि मराठाओं के कुनबी रिकॉर्ड खोजने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) संदीप शिंदे को भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा लिए जाने वाले वेतन

से लगभग दोगुना वेतन मिल रहा है। उन्होंने इसे अनावश्यक खर्च बताया है।

उन्होंने दावा किया कि एक बार जब वे ओबीसी के लिए मौजूदा आरक्षण का हिस्सा बन जाएंगे तो केवल उन्हें ही लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जो कुछ भी कह रहे हैं, उससे हमारा मन संतुष्ट नहीं है।

समिति के अध्यक्ष के वेतन पर उठाए सवाल

उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी के अनुसार, भारत के मुख्य न्यायाधीश को 2.80 लाख रुपये वेतन मिलता है, जबकि समिति का नेतृत्व कर रहे अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) संदीप शिंदे को 4.50 लाख रुपये मिलते हैं। इतना खर्च क्यों हो रहा है।

मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक फैसल शेख ने सोमानी प्रिन्टिंग प्रेस, गाला नं.4, एन. के. इंडस्ट्रीयल इस्टेट, प्रवासी इंडस्ट्रीयल इस्टेट के अंदर, गेट नं. 2, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई- 400063 से छपवाकर रूम नं 15 रमजान बिन 17 सी वंजावडी, माहिम वेस्ट मुंबई :4000 16 से प्रकाशित किया। संपर्क कार्यालय : शॉप नंबर ४ , मदीना मेंशन, ८९ ए, कैडल रोड, अपोजिट बिल्लाबोंग स्कूल, माहिम पश्चिम, मुंबई ४०००१६ , महाराष्ट्र मोबाइल नं 998777 5650 व्हाट्सप्प नं 7977408589: Email-editor@rokthoklekhaninews.com